सफलता की कुंजी

कुछ पल बैठा करो
बुजुर्गों के पास
हर चीज गूगल
पर नहीं मिलती

सच कहने की ताकत

जालंधर ब्रीज

साप्ताहिक समाचार पत्र

अनमोल वचन

जिस धागे की गांठें
खुल सकती हैं
उस धागे पर
कैंची नहीं चलानी चाहिए

• JALANDHAR BREEZE • WEEKLY • YEAR-1 • 5 FEBUARY TO 11 FEBUARY 2020 • VOLUME-23 • PAGES- 4 • RATE- 3/- • www.jalandharbreeze.com • RNI NO.:PUNHIN/2019/77863

बजट पर भ्रम फैलाने की कोशिश की गई, जनता को समझ आ गया कि बजट अच्छा है: मोदी

■ नई दिल्ली/ब्यूरो

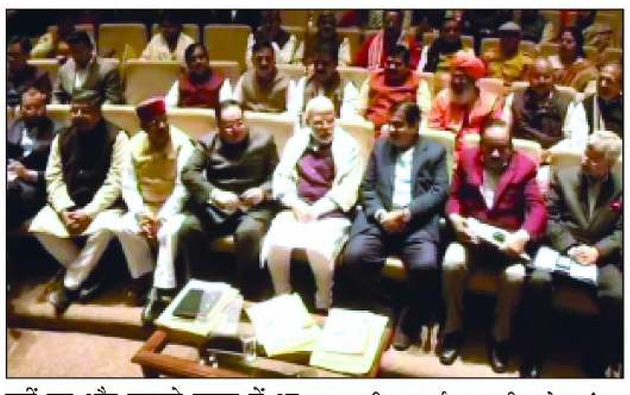

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को पार्टी सांसदों से कहा कि कुछ लोगों ने बजट पर भ्रम फैलाने की कोशिश की लेकिन जनता भ्रमित नहीं हुई और सबको समझ में आ गया कि बहुत अच्छा बजट है। सूत्रों ने यह जानकारी दी।सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने भाजपा संसदीय दल की बैठक में बोडो समझौते को बहुत महत्वपूर्ण बताया और कहा कि पहले की सरकारों ने कभी भी इस पर ध्यान नहीं दिया था।

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर की जनजातियों को असम में बसाने को लेकर जानकारी दी और कहा कि यह एक महत्वपूर्ण फैसला है। मोदी ने कहा कि कुछ लोगों ने बजट को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश तो हुई लेकिन लोग भ्रमित नहीं हुए और सबको समझ में आ गया कि बहुत अच्छा बजट है। भाजपा संसदीय दल की बैठक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हुए। पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद नड्डा पहली बार भाजपा संसदीय दल की बैठक में शामिल हुए।

सूत्रों ने बताया कि नड्डा ने कहा कि दिल्ली के चुनाव में सांसदों की ड्यूटी लगाई जाएगी। ये सांसद अगले कुछ दिन तक अलग अलग क्षेत्रों में रह कर पार्टी उम्मीदवारों के लिये प्रचार करेंगे। संसद भवन परिसर संसद ग्रंथालय में भाजपा संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जे पी नड्डा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आदि शामिल थे।

कोरोना वायरस: एयर इंडिया की दिल्ली-हांगकांग उड़ान आठ फरवरी से निलंबित

■ नई दिल्ली/ब्यूरो

हांगकांग में कोरोना वायरस से एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि होने के बाद एअर इंडिया ने आठ फरवरी से अपनी दिल्ली-हांगकांग उड़ान सेवा निलंबित करने की मंगलवार को घोषणा की।

कंपनी के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक अश्विनी लोहानी ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, " कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए सात फरवरी को एआई 314 को रवाना करने के बाद एअर इंडिया अपनी हांगकांग की उड़ानों को निलंबित कर रहा है।"

कोरोना वायरस का सबसे पहले मामला चीन के वुहान शहर से सामने आया था। कोरोना वायरस के कारण दुनियाभर में 400 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीमारी से मंगलवार को हांगकांग में भी एक व्यक्ति की मौत होने की सूचना मिली है। कंपनी ने इसके बाद अपनी हांगकांग की उड़ान रद्द करने का फैसला किया है। इससे पहले इंडिगो भी भारत से चीन के बीच की अपनी उड़ानें रद्द कर चुका है।

भाजपा में कोई नहीं जिसने पाकिस्तान में 'हिंदुस्तान जिंदाबाद' का नारा लगाया, हमारे उम्मीदवार ने कर दिखाया- राहुल

■ नई दिल्ली/ब्यूरो

दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जंगपुरा में पहली चुनावी रैली को संबोधित किया और बीजेपी-आम आदमी पार्टी पर नफरत फैलाने के आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बारे में झूठ बोल कर पीएम मोदी, अरविंद केजरीवाल ने सत्ता हासिल की. नफरत के माहौल से पीएम मोदी को फायदा लेकिन देश को नहीं. विकास के लिए नफरत मिटाना जरूरी है। जंगपुरा विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार तरविंदर सिंह मारवाह का परिचय कराते हुए राहुल गांधी ने कहा, इन्होंने पाकिस्तान में जा कर हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया और जेल गए. राहुल गांधी ने पूछा कि, क्या कोई बीजेपी नेता पाकिस्तान जा कर हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा सकता हैं? राहुल गांधी ने कहा, हमारे इतिहास में नफरत की जगह नहीं है, हमारा देश प्रेम वाला देश है; वे (बीजेपी) धर्म की बात करते हैं लेकिन कोई धर्म हिंसा की बात नहीं करता है. पीएम मोदी और आरएएस का यह किस तरह का "हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म सभी को साथ लेकर चलने की बात करता है। राहुल गांधी ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यह बताने को तैयार नहीं हैं कि कितने युवाओं को रोजगार मिला है. उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर सरकारी उपक्रमों को बेचने का आरोप लगाते हुए कहा कि वह ताजमहल भी बेच सकते हैं. राहुल ने कहा, केन्द्र सरकार अडानी और अंबानी के लिए है, यह सरकार सिर्फ 15 लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि वह दो करोड़ नौकरियां देंगे, उन्होंने इसके लिए क्या किया, केजरीवाल ने बेरोजगारी से निपटने के लिए क्या किया? विश्वविद्यालयों, कॉलेजों से स्नातक कर निकल रहे युवा डरे हुए हैं कि उन्हें नौकरी मिलेगी या नहीं, यह आपके प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का दोष है। दिल्ली में छह फरवरी को चुनाव प्रचार थमेगा और आठ फरवरी को वोट डाले जाएंगे. वोटों की गिनती 11 फरवरी को होगी।

गृह मंत्रालय ने संसद में साफ कहा, एन.आर.सी. को देशभर में लागू करने का फैसला अभी नहीं

■ नई दिल्ली/ब्यूरो

देश के कई स्थानों पर संशोधित नागरिकता कानून(सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के विरोध में हो रहे प्रदर्शनों के बीच सरकार ने

मंगलवार को लोकसभा में कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर एनआरसी लाने के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सदन में चंदन सिंह और नमा नागेश्वर राव के प्रश्नों के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। राय ने कहा, "अभी तक एनआरसी को राष्ट्रीय स्तर पर तैयार करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।" सदस्यों ने सवाल किया था कि क्या सरकारकी पूरे देश में एनआरसी लाने की कोई योजना है?

बाजार में लौटी हरियाली, सेंसेक्स 917 अंक ऊपर 40,789 पर, निफ्टी 2.33 फीसदी की तेजी पर बंद

■ नई दिल्ली/ब्यूरो

बजट के दो दिन बाद घरेलू शेयर बाजार में तेजी के जरिए बजट के दिन में आई गिरावट को पूरी तरह रिकवर कर लिया गया है। आज शेयर बाजार में 2.3 फीसदी से ज्यादा का उछाल देखा गया है और सेंसेक्स में तो 900 अंकों से ज्यादा का उछाल दर्ज किया गया है. बाजार में तेजी के पीछे ब्रेंट क्रूड में आई गिरावट को बड़ी वजह बताया जा रहा है। आज इसमें करीब 4 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है जो कि एक साल का निचला स्तर है।

कैसे बंद हुआ बाजार

आज के कारोबार में बीएसई का 30 शेयरों वाला इंडेक्स सेंसेक्स 917.07 अंक यानी 2.30 फीसदी की शानदार उछाल के बाद 40,789.38 पर जाकर बंद हुआ है और इसके अलावा एनएसई का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 273.15 अंक यानी 2.33 फीसदी की बढ़त के बाद 11,981.05 फीसदी पर जाकर बंद हुआ है।

बाजार के अन्य घटक

आज निफ्टी मिडकैप 50 में भी 1.44 फीसदी की शानदार तेजी के साथ कारोबार बंद हुआ है और इसके साथ ही बैंक निफ्टी में भी 2.21 फीसदी की बड़ी तेजी के साथ कारोबार बंद हुआ है।

सेक्टोरियल इंडेक्स

आज के सेक्टरवार कारोबार को देखें तो सबसे ज्यादा 3.32 फीसदी की तेजी मेटल शेयरों में देखी गई और रियलटी शेयर 2.77 फीसदी की उछाल के साथ बंद हुए हैं। फाइनेंशियल सेक्टर में 2.87 फीसदी

की बढ़त के साथ ट्रेडिंग खत्म हुई है और इसके साथ आईटी शेयरों में 1.81 फीसदी तो ऑटो शेयरों में 1.41 फीसदी की मजबूती के साथ कारोबार बंद हुआ है।

निफ्टी के सबसे ज्यादा चढ़ने वाले/गिरने वाले शेयर

निफ्टी के सबसे ज्यादा चढ़ने वाले शेयरों की बात करें तो टाइटन में 7.27 फीसदी और आईओसी में 5.55 फीसदी की उछाल दर्ज की गई। इसके साथ ही बजाज फिनसर्व 5.08 फीसदी और भारती इंफ्राटेल 4.84 फीसदी की मजबूती के साथ बंद हुए। वहीं बीपीसीएल में 4.27 फीसदी की बढ़त रही। सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयरों की बात करें तो ज़ी का शेयर 5.36 फीसदी, बजाज ऑटो 3.94 फीसदी, यस बैंक 2.78 फीसदी और आयशर मोटर्स 1.81 फीसदी की गिरावट पर बंद हुए। वहीं एफएमसीजी दिग्गज एचयूएल 1.23 फीसदी की कमजोरी के साथ लाल निशान में बंद हुआ है।

जमानत मिलने के बावजूद रिहा नहीं हुए हैं चिन्मयानंद

शाहजहांपुर/ब्यूरो

पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री स्वामी चिन्मयानंद को छात्रा के यौन शोषण के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय से जमानत मिलने के बावजूद अभी वह जेल से रिहा नहीं हुए हैं। हालांकि जमानत की सूचना पहुंचने के साथ ही उनके कॉलेज परिसर में खुशी का माहौल है और मिठाईयां बांटी जा रही हैं। स्वामी चिन्मयानंद के परिवार के सदस्य अमित सिंह ने मंगलवार को बताया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जमानत याचिका मंजूर की ली है लेकिन वहां से जमानत प्रपत्र अभी तक नहीं आ पाए हैं। जमानत प्रपत्र आने के बाद ही उन्हें यहां की अदालत में दाखिल किया जाएगा, जिसके बाद तमाम औपचारिकताएं पूरी होंगी।

रिहाई उसके बाद ही होगी। प्रक्रिया पूरी होकर रिहाई होने में थोड़ा वक्त लगेगा। सिंह ने बताया कि जमानत मंजूर होने के बाद उन्होंने जेल में चिन्मयानंद से मुलाकात की थी। वह काफी खुश नजर आ रहे थे। उन्होंने बताया, लोगों ने चिन्मयानंद को सलाह दी थी कि वह जेल से रिहाई के बाद हनुमंत धाम जाकर दर्शन करें और फिर अयोध्या जाएं। लेकिन उन्होंने अभी तक इसपर विचार नहीं किया है। चिन्मयानंद की जमानत मंजूर होने के बाद 'मुमुक्षु आश्रम' में आज हर्ष का माहौल था। लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे थे।

क्या लाखों रुपये वेतन पाने वाले अभियंताओं की कार्यशैली संदेहजनक ?

यहां दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है?

नैशनल हाईवे विभाग

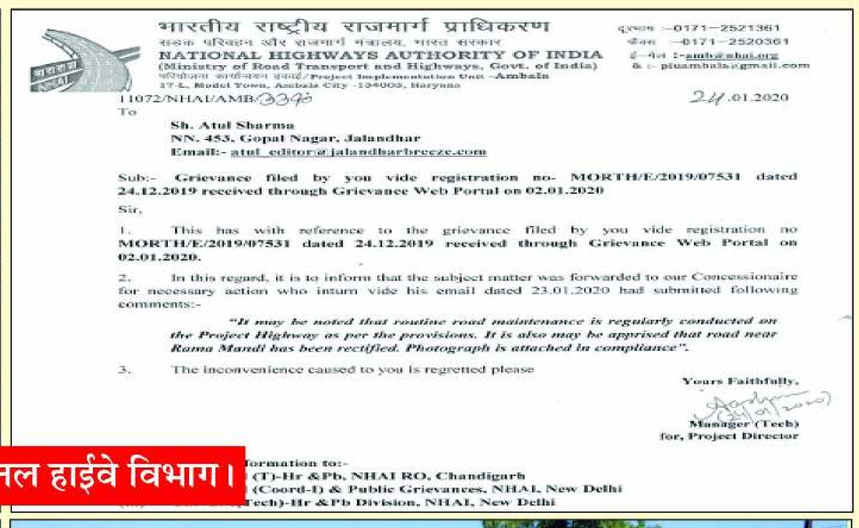

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार
NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA
(Ministry of Road Transport and Highways, Govt. of India)
परियोजना कार्यान्वयन इकाई/Project Implementation Unit -Ambala
17-L, Model Town, Ambala City -134003, Haryana

दूरभाष :-0171-2521361
फैक्स -0171-2520361
ई-मेल :-amb@nhai.org
& :- piuambala@gmail.com

11072/NHAI/AMB/3346

24.01.2020

To

Sh. Atul Sharma
NN. 453, Gopal Nagar, Jalandhar
Email:- atul_editor@jalandharbreeze.com

Sub:- Grievance filed by you vide registration no- MORTH/E/2019/07531 dated 24.12.2019 received through Grievance Web Portal on 02.01.2020

Sir,

1. This has with reference to the grievance filed by you vide registration no MORTH/E/2019/07531 dated 24.12.2019 received through Grievance Web Portal on 02.01.2020.

2. In this regard, it is to inform that the subject matter was forwarded to our Concessionaire for necessary action who inturn vide his email dated 23.01.2020 had submitted following comments:-

"It may be noted that routine road maintenance is regularly conducted on the Project Highway as per the provisions. It is also may be apprised that road near Rama Mandi has been rectified. Photograph is attached in compliance".

3. The inconvenience caused to you is regretted please

Yours Faithfully,

Manager (Tech)
for, Project Director

...formation to:-
... (T)-Hr &Pb, NHAI RO, Chandigarh
... (Coord-I) & Public Grievances, NHAI, New Delhi
... (Tech)-Hr &Pb Division, NHAI, New Delhi

दो महीने पहले बनी नई सड़क पर पैच वर्क लगाने की खुद ही पुष्टि करता हुआ नैशनल हाईवे विभाग।

जालंधर-पठानकोट रोड़ पर बीच में ही छोड़ा गया लोहे की ग्रिलों का काम।

■जालंधर से विजय कुमार की विशेष रिपोर्ट

वैसे तो राष्ट्रीय राजमार्ग प्रधिकरण त्रुटिपूर्ण कार्य करने का आदी है परन्तु साथ ही त्रुटियों को दूर करने में भी सिद्धहस्त हैं जैसे की रोड़ पर बनने वाले डिवाइडरस पर पहले तो ग्रिलस न लगाकर कुछेक लगाकर कार्य की इतिश्री कर देना और अगर किसी संस्था या समाचार-पत्र अथवा मीडिया द्वारा त्रुटि संबंधी कार्यवाही करने हेतु लिखा अथवा संज्ञान लिया जाता है तो उसे पुर्न निर्माण पूरा कर देने में भी पूर्ण सिद्धहस्त है चाहे वह अधूरा ही हो जैसेकि पठानकोट हाईवे 44 पर अधूरी ग्रिल्स लगाकर छोड़ देना रामामंडी में बने फ्लाई ओवर ब्रिज पर नवनिर्मित सड़क का टूट या बैठ जाना और उस पर पुन:पैच वर्क कर छोड़ देना खेद्जनक विषय तो यह है कि नवनिर्मित सड़क का कुछ ही दिनों में इस प्रकार बैठ जाना और फिर उस पर पैच लगा देना क्या सरकार में बैठे लाखों रुपये वेतन पाने वाले अभियंताओं की कार्यशैली संदेहजनक नहीं कि नवनिर्मित सड़क पर पैचवर्क करवाने के लिए उत्तरदायी कौन है कैसी निर्माण सामग्री का प्रयोग हुआ।

इस अतिसंवेदनशील मार्ग पर क्या यहाँ भी दुर्घटना संभावित मार्ग लिख भर देने से राजमार्ग प्राधिकरण का उत्तरदायित्व पूरा हो गया क्या हाइवे पैट्रोलिंग पार्टी ऐसी त्रुटियों को नजरन्दाज करती रहेगी प्रतिष्ठित अस्पताल हो या होटल,ढाबे, मॉल के पास बनी सड़क से डिवाइडर ग्रिलस क्यों गायब होती है और अब तो हाईवे पर भी रेहड़ी ठेले लगने लगे हैं। इनके समक्ष बने राजमार्ग की और जगह-जगह डिवाइडर ग्रिलस को तोड़ने वालों और रेहड़ी ठेले वालों पर पैट्रोलिंग पुलिस और हाईवे पैट्रोलिंग पार्टियां कार्यवाही क्यों नहीं करती? क्या यहां दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है।

उक्ति

जिस समाज में धार्मिक क्रियाकलापों का राजनीतिक इस्तेमाल होने लगे, वह धीरे-धीरे कमजोर होता जाता है। राजनीति और धर्मों के बीच एक सम्मानजनक दूरी जरूरी है।

■ नेल्सन मंडेला

www.jalandharbreeze.com

साप्ताहिक
5 फरवरी से 11 फरवरी 2020
जालंधर ब्रीज

पहल

किसानों पर मेहरबान सरकार

खेती और किसान के लिए यह वक्त जितना संघर्ष से भरा हुआ है, उससे ज्यादा संघर्ष से भरा भविष्य व्यापक समाज और माध्यम वर्ग के लिए होने वाला है। यह जरूरी ही नहीं अनिवार्यता है कि कृषि और कृषक के जीवन में आ रहे बदलावों से सक्रिय जुड़ाव रखा जाए। इसी को मद्देनजर रखते हुए मोदी सरकार ने बजट में किसानों के लिए प्रावधान किए हैं। उम्मीद करनी चाहिए कि इनसे किसानों के बुरे दिन दूर होंगे।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को वित्त वर्ष 2020-21 का बजट पेश किया, जिसमें उन्होंने किसानों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में एक बड़ी घोषणा की है। वित्त मंत्री ने फल, सब्जियां और मांस जैसे जल्दी खराब होने वाले कृषि उत्पादों की ढुलाई के लिए किसान रेल का प्रस्ताव किया है। इसके तहत, इन उत्पादों को ट्रेन के रेफ्रिजरेटेड डिब्बों में ले जाने की सुविधा होगी। हालांकि, यह कोई नई पहल नहीं है, क्योंकि इससे पहले साल 2004 में तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने भी इसी तरह की योजना की शुरुआत की थी, लेकिन नाकाम होने पर इसे बाद में बंद करना पड़ा था। अब वही सवाल फिर सिर उठा रहा है कि जब यह योजना पहले परवान नहीं चढ़ पाई है, फिर वही गलती करने की क्या जरूरत है। बहरहाल, पिछले अनुभवों से तो यह तय है कि इस योजना को परवान चढ़ाना इतना आसान नहीं होगा और यह बड़ी चुनौती होगी।

किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए उनके उत्पादों का बाजार बढ़ाने के लिए सब्जियों, फलों तथा मांस जैसे कृषि उत्पादों की दूर-दूर तक ढुलाई के लिए रेफ्रिजरेटेड डिब्बों का प्रस्ताव किया गया है। विशेष किसान रेलगाड़ियां सार्वजनिक-निजी भागीदारी के तहत चलाने का प्रस्ताव है। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए किसानों के लाभ के लिए कई उपायों का प्रस्ताव किया। उन्होंने कहा कि जल्द खराब होने वाले सामान के लिए राष्ट्रीय शीत आपूर्ति श्रृंखला के निर्माण को लेकर रेलवे पीपीपी मॉडल में किसान रेल बनाएगी। इससे ऐसे उत्पादों की ढुलाई तेजी से हो सकेगी। वित्त मंत्री निर्मला ने बजट भाषण में कहा कि सरकार का चुनिंदा मेल एक्सप्रेस और मालगाड़ियों के जरिए जल्द खराब होने वाले सामान की ढुलाई के लिए रेफ्रिजरेटेड पार्सल वैन का भी प्रस्ताव है। जल्द खराब होने वाले फलों, सब्जियों, डेयरी उत्पादों, मछली, मांस आदि को लंबी दूरी तक ले जाने के लिए इस तरह की तापमान नियंत्रित वैन की जरूरत है।

बता दें कि लालू यादव ने बिहार के कृषि उत्पादों का बाजार बढ़ाने के लिए रेफ्रिजरेटेड वैन योजना की शुरुआत की थी। उन्होंने 20 जून, 2004 को पटना से दिल्ली के बीच चलने वाली ट्रेन जनसाधारण एक्सप्रेस में लगे दूध और सब्जियों से लदे एक रेफ्रिजरेटेड कोच को राजेंद्र नगर टर्मिनल से हरी झंडी दिखाकर नई दिल्ली के लिए रवाना किया था। लेकिन यह योजना कुछ ही महीनों बाद बंद हो गई। इसी तरह, पटना से हावड़ा के बीच भी ट्रेनों में इस तरह के रेफ्रिजरेटेड वैन जोड़कर चलाए गए, लेकिन कुछ महीनों में यह भी बंद हो गए। इन रेफ्रिजरेटेड वैन में सब्जियां और दूध की ढुलाई होती थी। कुछ महीने तक तो किसी तरह यह योजना चली, लेकिन बाद में यह भी बंद हो गई। दरअसल, इसके बंद होने के पीछे कई कारण थे। सबसे पहला कारण इसका व्यवहार्य नहीं होना था। गांवों से बड़े बाजारों तक माल पहुंचने में लंबा वक्त लग जाता था, उसके बाद उन्हें रेफ्रिजरेटेड वैन में लोड होने में वक्त लगता था और फिर माल को गंतव्य तक पहुंचने में भी वक्त लग जाता था। चूंकि ये उत्पाद सड़ने वाले थे, इसलिए गंतव्य तक पहुंचने से पहले ही इनकी गुणवत्ता खराब हो जाती थी, जिसके कारण बाजार में इन्हें कोई पूछने वाला नहीं होता था।

मूलतः इसी कारण से यह योजना परवान नहीं चढ़ सकी। सरकार की इस घोषणा में अगर-मगर के प्रश्न जरूर हैं, लेकिन इस योजना को अभी से खारिज किया जाना ठीक नहीं होगा। लालू के कार्यकाल की योजना की नाकामी का पता सरकार को है। अगर यह जानते हुए भी इसे फिर से साकार किया जा रहा है तो पूरे अध्ययन के बाद। सरकार को इस योजना को मूर्तरूप देने का समय देना होगा और इंतजार करना होगा। हो सकता है कि इस बार यह योजना वाकई काम कर जाए। इसके अलावा बजट में किसानों को एक और राहत दी गई है। अब किसानों का सामान विमान से जाएगा। इसके अलावा सरकार उन राज्यों को प्रोत्साहित करेगी जो केंद्र के मॉडल लॉ को मानेंगे। पंप सेट को सौर ऊर्जा से जोड़ने का प्रयास, 20 लाख किसानों को सोलर प्लांट दिए जाएंगे। पानी की कमी की समस्या, 100 ऐसे जिलों के लिए प्रयास किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि अन्नदाता ऊर्जादाता भी है। पीएम कुसुम स्कीम से फायदा हुआ है। अब हम 20 लाख किसानों को सोलर पंप देंगे। कुल 15 लाख किसानों को ग्रिड कनेक्टेड पंपसेट से जोड़ा जाएगा। 162 मिलियन टन के भंडारण की क्षमता है। नाबार्ड इसे जियोटैग करेगा। नए बनाए जाएंगे। ब्लॉक और ताल्लुक के स्तर पर बनेंगे। सरकार जमीन दे सकती है। एफसीआई अपनी जमीन पर भी बना सकती है।

सीतारमण ने बजट में महात्मा गांधी की बातों को याद दिलाकर उसे दोहराया। उन्होंने कहा कि असल भारत गांव में बसता है गांव और किसान उनकी हर योजना का केंद्र बिंदु होगा। इसके अलावा किसानों को व्यापार करने और जीवन को आसान करने के लिए के लिए कई महत्वपूर्ण कदम सरकार उठाएंगी। उन्होंने कहा कि किसानों को उस स्थिति में पहुंचाना है जहां पर जीरो बजट पर खेती कर सके। इस तरह की खेती से उन्हें किसी भी प्रकार के बाजार पर निर्भर नहीं होना पड़ता है जो बेहद सस्ती भी है। वित्तमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार कृषि क्षेत्र के बुनियादी ढांचे में निवेश कर रही है। दस हजार नई किसान उत्पादक कंपनी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वित्तमंत्री ने कहा कि दस हजार नए किसान उत्पादक संगठन बनाए जाएंगे। भारत जिस तरह से दाल में आत्मनिर्भर हो गया है उसी तर्ज पर हम तिलहन में भी कामयाबी हासिल करेंगे।

यह पहले से माना जा रहा था कि मोदी सरकार बजट में किसानों के लिए खास प्रावधान करेगी। किसानों की आय दोगुनी करने का जो लक्ष्य लेकर चल रही है, उसकी मियाद खत्म होने में अब सिर्फ दो साल का वक्त बचा है। सरकार जानती है कि अगर किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करनी है तो सबसे पहले उनकी फसल को बेहतर माहौल देना होगा। अगर किसान अपनी उपज को लेकर परेशान नहीं होगा तो वह आसानी से अपनी आय में इजाफा कर सकता है। अभी जिस तरह से बाजार में बिचौलियों का जाल बिछा है, उससे किसानों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार को इस दिशा में भी सोचना होगा। हालांकि, बिचौलियों का कब्जा खत्म करने की दिशा में भी बजट में ऐलान किए गए हैं, मगर यह इतना भी आसान नहीं है, जिनता सोचा जा रहा है। लिहाजा सरकार को इस दिशा में काफी काम करने की जरूरत है।

खेती और किसान के लिए यह वक्त जितना संघर्ष से भरा हुआ है, उससे ज्यादा संघर्ष से भरा भविष्य व्यापक समाज और माध्यम वर्ग के लिए होने वाला है। यह जरूरी ही नहीं अनिवार्यता है कि कृषि और कृषक के जीवन में आ रहे बदलावों से सक्रिय जुड़ाव रखा जाए। भारत में 2017 में एक किसान परिवार की मासिक आय 8,931 रुपए थी। भारत में किसान परिवार में औसत सदस्य सख्या 4.9 है, यानी प्रति सदस्य आय 61 रुपए प्रतिदिन है। बुनियादी बिंदु यह भी है कि किसानों की आय में वृद्धि का बाजार की कीमतों और गरिमामय जीवनयापन के लिए जरूरी आय से क्या संबंध होगा? इस पर भी गौर किया जाना बेहद जरूरी है। देखना होगा कि बजट के प्रावधान किसानों की जिंदगी पर क्या असर डालते हैं।

■ ज्योति मांझी
(वरिष्ठ पत्रकार)

विचार

बजट से कोई खुश तो कोई...

आम बजट में किए गए ऐलानों का असर आने वाले दिनों में भले अर्थव्यवस्था को कुछ रफ्तार के तौर पर देखा जा सकता है, लेकिन रोजगार के मोर्चे पर कई लोगों को निराशा है। सरकार कह रही है कि रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, मगर कैसे, यह देखने वाला होगा।

आम बजट में किए गए ऐलानों का असर आने वाले दिनों में भले अर्थव्यवस्था को कुछ रफ्तार के तौर पर देखा जा सकता है, लेकिन फिलहाल तो उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। सबसे ज्यादा निराशा ऑटो मोबाइल इंडस्ट्री को हुई है। कहा जा रहा है कि यह वो बजट नहीं था जिसकी उन्हें उम्मीद थी। बजट से उम्मीद की जा रही थी कि सरकार कुछ सीधी फायदे इंडस्ट्री को देगी जिससे मांग बढ़ेगी और इंडस्ट्री मौजूदा मंदी के दौर से उबर पाएगी लेकिन बजट भाषण से सारी बातें नदारद रहीं। अभी केंद्र सरकार ने खर्च में अगले वित्त वर्ष में 13 फीसदी इजाफे का ऐलान किया है। उनके मुताबिक खर्च मौजूदा अर्थिक हालात के हिसाब से अच्छा स्टिमुलस नहीं कहा जा सकता है। सरकार को आने वाले दिनों में ऐलानों पर और सफाई देने से हालात कुछ बदल सकते हैं। बहरहाल, बजट से ज्यादा उम्मीदें अब नहीं करनी चाहिए। सरकार ने पिछले कई सालों में बजट से बाद भी तमाम बड़े ऐलान किए हैं जिनका अर्थ्यवस्था पर प्रभाव देखने को मिला है।

इस बार बजट से तमाम स्टिमुलस पैकेज को लेकर उम्मीदें लगी हुई थीं जिनको निश्चित तौर पर झटका लगा है। देश मे इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के खर्च से जुड़ी बड़ी घोषणा का ऐलान न होना भी चिंताजनक रहा। हालांकि, सरकार ने भारतनेट के लिए जो ऐलान किए हैं वो देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचाएगा। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार की तरफ से और निवेश की जरूरत है। मेक इन इंडिया के जरिए उत्पादन करने से देश को असली फायदा होगा। असेंबलिंग यूनिटें लगाने से मेक इन इंडिया की तुलना में कम मुनाफा होगा। अगर रोजगार की बात करें तो केंद्र सरकार ने युवाओं के कौशल विकास के लिए करीब तीन हजार करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की है। लेकिन खुद युवाओं का कहना है कि सरकार ने बजट में रोजागार को लेकर प्रावधान नहीं किया गया है। भले ही सरकार शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा दे रही है। पर रोजगार सृजन को लेकर भी सरकार को बजट में प्रावधान करना चाहिए था।

आखिर पढ़ाई पूरी करने के बाद युवाओं को एक बेहतर नौकरी की तलाश होती है और रोजगार उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी सरकार की बनती है। आज देश में बड़ी संख्या में ऐसे युवा हैं, जिन्होंने आईटीआई, पॉलटेक्निक और अन्य कौशल विकास केंद्रों से प्रशिक्षण लिया है। पर कुछ फीसद ही युवाओं को ही बेहतर नौकरी मिली है। केंद्र और कई राज्य सरकार भी कौशल विकास के कार्यक्रम चला रहे हैं, लेकिन बीते कुछ महीने में देश में बेरोजगारी बढ़ी है। अगर प्रशिक्षण लेने के बाद भी नौकरी नहीं मिलेगी तो देश का युवा तकनीकि शिक्षा या फिर उच्च शिक्षा लेकर क्या करेगा? केंद्र सरकार को इस बारे में सोचना ही पड़ेगा। वैसे, सरकार कह रही है कि बजट के ऐलानों से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, मगर कैसे, यह देखने वाला होगा। हो सकता है कि जादू असर कर जाए।

पॉक्सो एक्ट को बनाएं मजबूत

भारतीय संस्कृति और परंपरा हमेशा से गौरवशाली रही है। हमारे परिवारों में बच्चों को देवतुल्य माना गया है। यह माना जाता है कि उनका मन कच्ची माटी सा होता है और उसे जिस सांचे में ढालो, वह वैसा ही बन भी जाता है। नन्हीं बच्चियों को लेकर हमारा समाज अपने जन्म से संवेदनशील रहा है लेकिन बदलते दौर में सारे मानक बदल रहे हैं और हमारी गौरवशाली संस्कृति और परंपरा को घात पहुंचा रहे हैं। इन विपरीत और शर्मनाक स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए कानून सख्त कदम उठाता रहा है। बच्चों के साथ जिस तरह से बर्बर यौन व्यवहार किया जा रहा है, वह समाज के लिए शर्मनाक है। बच्चों को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए 2012 में एक कानून बनाया गया था जिसे पॉक्सो कानून यानी की प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल अफेंसेस एक्ट 2012 जिसको लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों के संरक्षण का अधिनियम 2012 कहा जाता है। इस कानून के बाद भी अपराधों में कमी नहीं आने के कारण कानून को और सख्त बनाया गया है। हाल ही में 2019 में पाक्सो एक्ट में संशोधन कर अपराधी को दंड दिए जाने के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं।

प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल अफेंसेस एक्ट 2012 के तहत अलग-अलग अपराध में पृथक-पृथक सजा का प्रावधान है। और यह भी ध्यान दिया जाता है कि इसका पालन कड़ाई से किया जा रहा है या फिर नहीं। इस अधिनियम में सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय बाल संरक्षण मानकों के अनुरूप प्रावधान है कि यदि कोई यह जानता है कि किसी बच्चे का यौन शोषण हुआ है तो उसे इसकी रिपोर्ट नजदीकी थाने में देनी चाहिए, यदि वो ऐसा नहीं करता है तो उसे छह महीने के कारावास और आर्थिक दंड से दंडित किया जा सकता है। 18 साल से कम किसी भी मासूम के साथ अगर दुराचार होता है तो वह पॉक्सो एक्ट के तहत आता है। इस कानून के लगने पर तुरंत गिरफ्तारी का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त अधिनियम की धारा 11 के साथ यौन शोषण को भी परिभाषित किया जाता है। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई भी व्यक्ति अगर किसी बच्चे को गलत नीयत से छूता (बेड टच करता) है या फिर उसके साथ गलत हरकतें करने का प्रयास करता है या उसे पोर्नोग्राफी दिखाता है तो यह धारा 11 के तहत दोषी माना जाएगा। इस धारा के लगने पर दोषी को तीन साल तक की सजा हो सकती है।

इस कानून की धारा चार में वो मामले आते हैं जिसमें बच्चे के साथ कुकर्म या फिर दुष्कर्म किया गया हो। इस अधिनियम में सात साल की सजा से लेकर

पाक्सो एक्ट को और सख्त बनाए जाने के बाद बच्चों को अधिक सुरक्षा की उम्मीद की जा सकती है। कानून के साथ-साथ इस दिशा में सामाजिक जागरूकता की भी आवश्यकता है। बच्चों के साथ दुर्व्यवहार रोकने के लिए सबको सजग होना होगा क्योंकि जागरूकता से ही अपराधों पर नियंत्रण पाया जा सकेगा। बच्चों के साथ होने वाले अपराधों पर नियंत्रण के लिए सरकारी पहल तब तक असर नहीं दिखाएगी, जब तक समाज अपने स्तर पर पहल नहीं शुरू करेगा।

उम्रकैद तक का प्रावधान है, साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। धारा छह के अंतर्गत वो मामले आते हैं जिनमें बच्चों के साथ कुकर्म, दुष्कर्म के बाद उनको चोट पहुंचाई गई हो। इस धारा के तहत 10 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान है साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अगर धारा सात और आठ की बात की जाए तो उसमें ऐसे मामले आते हैं जिनमें बच्चों के गुप्तांग में चोट पहुंचाई जाती है। इसमें दोषियों को पांच से सात साल की सजा के साथ जुर्माना का भी प्रावधान है। पाक्सो एक्ट बाल संरक्षक की जिम्मेदारी पुलिस को सौंपता है। इसमें पुलिस को बच्चे की देखभाल व संरक्षण के लिए तत्काल व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी दी जाती है। जैसे बच्चे के लिए चिकित्सा उपचार प्राप्त करना और बच्चे को आश्रय गृह में रखना इत्यादि।

पुलिस की यह जिम्मेदारी बनती है कि मामले को 24 घंटे के अंदर बाल कल्याण समिति की निगरानी में लाए जिससे समिति बच्चे की सुरक्षा और संरक्षण के लिए जरूरी कदम उठा सके। इस अधिनियम में बच्चे की मेडिकल जांच के लिए प्रावधान भी किए गए हैं। यह भी निर्देश हैं कि जांच बच्चे के लिए कम से कम पीड़ादायक हो। मेडिकल जांच बच्चे के माता-पिता या किसी अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में किया जाना चाहिए, जिस पर बच्चे का विश्वास हो और बच्ची की मेडिकल जांच महिला चिकित्सक द्वारा की जानी चाहिए। इस बात का ध्यान रखा गया है कि न्यायिक व्यवस्था के द्वारा फिर से बच्चे पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं बनाया जाए। इस नियम में केस की सुनवाई एक विशेष अदालत द्वारा बंद कमरे में कैमरे के सामने दोस्ताना माहौल में किया जाने का प्रावधान है। इस दौरान बच्चे की पहचान गुप्त रखने की कोशिश की जानी चाहिए। पुलिस की यह जिम्मेदारी बनती है कि मामले को 24 घंटे के अंदर बाल कल्याण समिति की निगरानी में लाए। विशेष न्यायालय, उस बच्चे को दिए जाने वाली मुआवजा राशि का निर्धारण कर सकता है, जिससे बच्चे के चिकित्सा उपचार और पुनर्वास की व्यवस्था की जा सके। अधिनियम में यह कहा गया है कि बच्चे के यौन शोषण का मामला घटना घटने की तारीख से एक वर्ष के भीतर निपटाया जाना चाहिए।

पॉक्सो अधिनियम में संशोधन बाल यौन अपराध के पहलुओं से उचित तरीके से निपटने के लिए किया गया है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि अधिनियम की धारा 4, 5 और 6 में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव किया गया है, ताकि बच्चों का आक्रामक यौन उत्पीड़न करने के मामले में मौत की सजा सहित कठोर सजा का प्रावधान हो सके। इसमें कहा गया है कि यह संशोधन, देश में बाल यौन अपराध की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को रोकने के लिए कठोर उपाय करने की जरूरत के तहत, किया जा रहा है। इसके मुताबिक अधिनियम में 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को बच्चा परिभाषित किया गया है। यह लैंगिक रूप से निरपेक्ष कानून है। संशोधन में प्राकृतिक संकटों और आपदाओं के समय बच्चों के यौन अपराधों से संरक्षण और आक्रामक यौन अपराध के उद्देश्य से बच्चों की जल्द यौन परिपक्वता के लिए उन्हें किसी भी तरीके से हार्मोन या कोई रासायनिक पदार्थ देने के मामले में अधिनियम की धारा 9 में संशोधन किया गया है। इस कानून के तहत बच्चों का यौन उत्पीड़न करने वाले दोषियों को उम्रकैद के साथ मौत की सजा का प्रावधान किया गया है।

बाल पोर्नोग्राफी की बुराई से निपटने के लिए पॉक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 14 और धारा 15 में भी संशोधन किया गया है। बच्चों से संबद्ध पोर्नोग्राफिक सामग्री को नष्ट नहीं करने पर जुर्माना लगाने का प्रस्ताव किया गया है। साथ ही, इस तरह की चीजों को अदालत में साक्ष्य के तौर पर पेश करने सहित कुछ मामलों को छोड़ कर अन्य किसी भी तरह के इस्तेमाल में जेल या जुर्माना, या दोनों सजा सकती है। पाक्सो एक्ट को और सख्त बनाए जाने के बाद बच्चों को अधिक सुरक्षा की उम्मीद की जा सकती है। कानून के साथ-साथ इस दिशा में सामाजिक जागरूकता की भी आवश्यकता है। बच्चों के साथ दुर्व्यवहार रोकने के लिए सबको सजग होना होगा क्योंकि जागरूकता से ही अपराधों पर नियंत्रण पाया जा सकेगा। बच्चों के साथ होने वाले अपराधों पर नियंत्रण के लिए सरकारी पहल तब तक असर नहीं दिखाएगी, जब तक कि समाज अपने स्तर पर पहल नहीं शुरू करेगा।

■ दुर्गेश रायकवार
(वरिष्ठ पत्रकार)

ट्विटर

बजट में विजन भी है, एक्शन भी है। सरकार का लक्ष्य किसानों की आय दोगुनी करना है। नौजवानों के लिए नए अवसर पैदा होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ेगा।

नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

बजट के नाम पर सिर्फ भाषण था। अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए में बजट में कुछ नहीं था। मुख्य मुद्दा बेरोजगारी है। बजट में सिर्फ आंकड़ों का जुमला था।

राहुल गांधी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष

सत्यार्थ

विलियम जोंस की लगन

बात आजादी से बहुत पहले की है। तब कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश सर विलियम जोंस हुआ करते थे। इंग्लैंड से जब उनका भारत आना हुआ, तो उन्होंने संस्कृत भाषा सीखने की सोची। लेकिन दिक्कत यह थी कि उसका कोई भी पंडित समाज में अपनी बदनामी के डर से उन्हें पढ़ाने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। जो मिल रहे थे, उनका ज्ञान संदिग्ध था। बहुत खोजने पर एक वैद्य जी पढ़ाने को तैयार तो हुए, लेकिन उन्होंने भी कई शर्तें लगा दीं। उन्होंने कहा- मैं कक्षा में बैठकर ही पढ़ाऊंगा और उसमें एक मेज एवं दो कुर्सियों के अलावा और कुछ भी नहीं होगा। कक्षा की सफाई सिर्फ हिंदू कर्मचारी ही करेगा और वह मेज कुर्सियों पर गंगाजल जरूर छिड़केगा। विलियम जोंस को मांस-मदिरा छोड़नी पड़ेगी। जोंस को पढ़ाने से पूर्व व पढ़ाने के पश्चात वैद्य जी कपड़े बदलेंगे और इसके लिए उनका अलग कक्ष होगा। मासिक दक्षिणा चांदी के सौ सिक्के रहेगी। उन्हें घर से लाने व वापस पहुंचाने के लिए पालकी की व्यवस्था करनी होगी। वैद्य जी ने यह सोचा था कि कठोर शर्तें सुनकर अंग्रेज पढ़ने का विचार त्याग देगा और बला टल जाएगी। पर जोंस संस्कृत सीखने का दृढ़ निश्चय कर चुके थे। सो, उन्होंने सारी शर्तें स्वीकार कर लीं। उनकी संस्कृत की पढ़ाई प्रारंभ हो गई। जोंस महोदय बड़े ही नम्र स्वभाव के सुशील छात्र थे। अपने व्यवहार, सेवा, परिश्रम और लगन से गुरु को प्रसन्न करके उनका दिल जीत ही लिया। वैद्य जी की पढ़ाई और अपने परिश्रम के बल पर धीरे-धीरे वे संस्कृत के प्रकांड विद्वान हो गए। उन्होंने संस्कृत में लिखे 'अभिज्ञान शाकुंतलम' नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद किया। उन्होंने मिसाल कायम की कि लगनशील व्यक्ति के लिए कुछ भी सीखना असंभव नहीं होता।

■ राधा नागीज

आमजन पर राहत की बौछार

करदाताओं को विकल्प चुनने का अधिकार, स्लैब में बदलाव

40000 करोड़ रुपए के राजस्व का होगा नुकसान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को करदाताओं को राहत देते हुए कर कानूनों को सरल बनाने के लिए नई वैकल्पिक व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था पेश की। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत कई तरह की छूट और कटौतियां नहीं मिलेगी। नए ढांचे में विभिन्न आयवर्ग के करदाताओं के लिए दरों में कटौती की गई है और कुछ नए स्लैब बनाए हैं। अनुमान है कि नई कर दरों से सरकारी खजाने को सालाना 40 हजार करोड़ रुपए के राजस्व से वंचित होना पड़ेगा। वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2020-21 का बजट पेश करते हुए कहा कि नई कर व्यवस्था वैकल्पिक होगी। करदाताओं को विकल्प दिया जाएगा कि वह चाहे तो छूट और कटौती के साथ पुरानी कर व्यवस्था में रहें या फिर बिना छूट वाले नए कर ढांचे को अपनाएं।

इनकम टैक्स के दो ऑप्शन जानें नए विकल्प के फायदे

ध्यान दें तो यह ऑफर उन लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगा जो अपनी कमाई का ज्यादा हिस्सा निवेश नहीं कर पाते हैं। नई व्यवस्था के तहत आप चाहें तो नए टैक्स स्लैब अपना सकते हैं या फिर पुरानी व्यवस्था के तहत ही टैक्स दे सकते हैं। इसका फैसला करते वक्त ध्यान रखना होगा कि आप इनकम टैक्स ऐक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत कितनी टैक्स छूट ले सकते हैं। अगर टैक्स छूट से ज्यादा बचत हो रही हो तो आपके लिए पुराना टैक्स स्लैब ही चुनना बेहतर होगा।

7.5 लाख तक की आमदनी वालों के लिए, अब

- पांच लाख रुपए तक की आमदनी पर 5 फीसदी की दर से 12500 रुपए।
- 5 से 7.5 लाख यानी 2.5 लाख रुपए पर नई टैक्स दर 10 फीसदी की दर से 25000 रुपए।
- कुल टैक्स - 37500 रुपए।
- सेस - 1500 रुपए।
- **टैक्स और सेस = 39000 रुपए**

पहले

- 5 लाख रुपए तक पर 5 फीसदी की दर से टैक्स 12500 रुपए
- 5 से 7.5 लाख तक के 2.5 लाख पर 20 फीसदी की दर से 50000 रुपए
- कुल टैक्स - 62500 रुपए
- सेस - 2500 रुपए
- टैक्स और सेस मिलाकर 65000 रुपए

फायदा : 65000 रुपए-39000 रुपए =26000 रुपए

10 लाख रुपए तक, अब

- 5 लाख रुपए तक 12500 रुपए
- 5 से 7.5 लाख तक के 2.5 लाख रुपए पर 10 फीसदी की दर से टैक्स 25000 रुपए
- 7.5 लाख से 10 लाख रुपए तक के 2.5 लाख रुपए पर 15 फीसदी की दर से 37500 रुपए टैक्स
- कुल टैक्स- 75000 रुपए
- सेस- 3000 रुपए
- **टैक्स व सेस =78000 रुपए**

पहले

- 5 लाख रुपए तक टैक्स 12500 रुपए
- 5 से 10 लाख तक के 5 लाख रुपए पर 20 फीसदी की दर से टैक्स एक लाख रुपए
- कुल टैक्स -112500 रुपए
- सेस : 4500 रुपए
- टैक्स व सेस = 117000 रुपए

फायदा : 117000 रुपए- 78000 रुपए = 39000 रुपए

12.5 लाख रुपए तक, अब

- 10 लाख रुपए से 12.5 लाख रुपए के 2.5 लाख रुपए पर 20 फीसदी की दर से 50000 रुपए
- कुल टैक्स - 125000 रुपए
- सेस - 5000 रुपए
- **टैक्स व सेस = 130000 रुपए**

पहले

- 10 से 12.5 लाख रुपए के 2.5 लाख रुपए पर 30 फीसदी की दर से 75000 रुपए
- कुल टैक्स - 137500
- सेस- 5500 रुपए
- टैक्स व सेस = 143000 रुपए

फायदा : 143000 रुपए- 130000 रुपए = 13000 रुपए

नई कर व्यवस्था और पुरानी कर व्यवस्था में आयकर में तुलनात्मक अध्ययन

क्रम	कुल आय	पुराना	नया	अंतर राशि	पुराना कर फीसदी
1	5,00,000	शून्य	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं
2	6,00,000	33,800	23,400	10,400	30.77
3	7,00,000	54,600	33,800	20,800	38.10
4	7,50,000	65,000	39,000	26,000	40.00
5	8,00,000	75,400	46,800	28,600	37.93
6	9,00,000	96,200	62,400	33,800	35.14
7	10,00,000	1,17,000	78,000	39,000	33.33
8	11,00,000	1,48,200	98,800	49,400	33.33
9	12,00,000	1,79,400	1,19,600	59,800	33.33
10	12,50,000	1,95,000	1,30,000	65,000	33.33
11	13,00,000	2,10,600	1,43,000	67,600	32.10
12	14,00,000	2,41,800	1,69,000	72,800	30.11
13	15,00,000	2,73,000	1,95,000	78,000	28.57

नई टैक्स छूट का लाभ उठाने के लिए छोड़नी होंगी 70 रियायतें!

नए टैक्स स्लैब के मुताबिक 5 लाख से 7.5 लाख रुपए तक की सालाना आय वालों को अब 20 फीसदी के मुकाबले सिर्फ 10 फीसदी की दर से ही टैक्स चुकाना होगा। वहीं, जिनकी सालाना आय 7.5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक है, उन्हें सिर्फ 15 फीसदी की दर से ही टैक्स भरना होगा। हालांकि, अगर आप नई दरों से कर अदायगी करते हैं तो आपको टैक्स में मिलने वाली करीब 70 रियायतों को छोड़ना पड़ेगा। पहले बीमा, निवेश, घर का रेंट, मेडिकल, बच्चों की स्कूल फीस जैसी कुल 100 रियायतें दी गई थीं जबकि अब नए टैक्स स्लैब में 70 रियायतों को खत्म कर दिया गया है।

क्या कहते हैं विश्लेषक

आर्थिक मामलों के जानकार कहते हैं, इनकम टैक्स में बड़े बदलाव के बाद टैक्स रियायतों के जरिए बचत प्रोत्साहित करने की नीति खत्म हो जाएगी। इससे बचत में गिरावट बढ़ेगी और बीमा, मेडिक्लेम, छोटी बचत स्कीमों पर भी इसका असर होगा। अगर होम लोन पर टैक्स छूट भी नई स्कीम का हिस्सा होती है तो हाउसिंग भी प्रभावित होगी। छूट रियायत की वापसी के बदले कर रियायत के बाद बीमा, यूलिप, रियल एस्टेट कारोबारों का बुरा हाल होगा।

जीएसटी रिटर्न का आसान फॉरमेट आएगा

फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने एक फरवरी 2020 को बजट पेश करते हुए जीएसटी को आसान करने का ऐलान किया। अपने दूसरे बजट में सीतारमण ने कहा कि अप्रैल 2020 से जीएसटी रिटर्न का आसान फॉरमैट उपलब्ध कराया जाएगा। एक जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था और तब से ही कारोबारी इसे लेकर परेशान हैं। निर्मला सीतारमण ने संसद में बताया कि जीएसटी की वजह से ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स सेक्टर को काफी फायदा हुआ है। इससे इंसपेक्टर राज से छुटकारा मिला है। जीएसटी से माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज एमएसएमई को फायदा हुआ है। ग्राहकों को सालाना एक करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। जीएसटी के तहत 60 लाख नए टैक्सपेयर्स और 105 करोड़ रुपए ई-वे बिल जेनरेट हुए हैं। वित्त मंत्री ने कहा, जीएसटी की वजह से औसत हाउसहोल्ड को अपने खर्चों में हर महीने चार फीसदी की बचत हुई है।

9000 करोड़ रुपए सीनियर सिटीजन के लिए आवंटित

डिपॉजिट पर इंश्योरेंस कवर एक लाख से बढ़ाकर पांच लाख किया गया

सरकार ने डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर एक लाख रुपए से प्रति डिपॉजिटर से बढ़ाकर पांच लाख रुपए प्रति डिपॉजिट करने का निर्णय लिया है। फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन ने ये जानकारी एक फरवरी को वित्त वर्ष 2020-2021 का यूनियन बजट पेश करते हुए दी। फाइनेंस मिनिस्टर ने आगे कहा कि सभी शेड्यूल्ड कर्मिशयल बैंकों के हालात की निगरानी के लिए देश में मजबूत मेकेनिज्म है, देश में जमाकर्ताओं की जमा पूंजी को कोई खतरा नहीं है। हाल में बैंकों, सहकारी बैंकों, नॉन बैंकिंग, फाइनेंस कंपनियों में हुए तमाम घोटालों के बाद जमाकर्ताओं में चिंता की स्थिति बन गई थी जिसको देखते हुए फाइनेंस मिनिस्टर की यह घोषणा जमाकर्ताओं के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। आरबीआई इम्प्लाई यूनियन ने भी मंगलवार को बैंक जमाओं पर बीमा कवर को वर्तमान एक लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने की मांग की थी। सरकार ने यह कदम पंजाब एंड महाराष्ट्र को-आपरेटिव बैंक के हालिया संकट के बाद इस तरह का कदम उठाना जरूरी हो गया था। अगर कोई बैंक डूब जाता है तो उसके जमाकर्ताओं को अधिकतम एक लाख रुपए की राशि सरकार देती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आम बजट में ऐलान के बाद अब बैंकों में जमा रकम पर अब पांच लाख रुपए की इंश्योरेंस गारंटी मिलेगी। बजट में ये भी कहा गया है कि जमाकर्ताओं के पैसे सुरक्षित हो, इसके लिए एक बेहतरीन तंत्र बनाया जा रहा है।

नॉन गजटेड पोस्ट पर भर्ती को नई एजेंसी

वित्त मंत्री ने कहा कि बैंकों में नॉन गजटेड पोस्ट पर नियुक्ति को लेकर समीक्षा की जा रही है। एक राष्ट्रीय रिक्रुटमेंट एजेंसी बनाई जाएगी ताकि नॉन गजटेड पोस्ट के लिए ऑनलाइन एक कॉमन रिक्रुटमेंट टेस्ट लिया जा सके और हर जिले में इसकी स्थापना की जाएगी।

नए विकल्प में नहीं होंगी यह रियायतें

नई टैक्स व्यवस्था में कम दर पर टैक्स भुगतान करने का विकल्प होगा, लेकिन इसमें किसी भी तरह का डिडक्शन का फायदा नहीं मिलेगा। टैक्सपेयर्स के लिए कौन सा विकल्प फायदेमंद होगा इसके लिए उन्हें नए तथा पुराने टैक्स विकल्प के तहत अपनी टैक्स देनदारी का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अगर आप पहले ही टैक्स सेविंग के लिए विभिन्न साधनों में निवेश कर चुके हैं और चाहते हैं कि डिडक्शन का फायदा लें तो आप पुराने वाले टैक्स विकल्प का ही चयन करें।

- वेतनभोगी कर्मचारियों को मिलने वाला लीव ट्रैवेल अलाउंट इग्जेंप्शन, हाउस रेंट अलाउंस इग्जेंप्शन।
- सैलराइड टैक्सपेयर्स को मिलने वाला 50 हजार रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन।
- आयकर अधिनियम के सेक्शन 16 के तहत इंटरटेनमेंट अलाउंस और एंप्लॉयमेंट, प्रफेशनल टैक्स के लिए डिडक्शन।
- खाली मकान के हाउजिंग लोन के इंट्रेस्ट पर मिलने वाला टैक्स बेनिफिट।
- इनकम टैक्स के सेक्शन 57 के क्लॉज पपं के तहत फैमिली पेंशन पर 15000 रुपए की टैक्स छूट।
- सेक्शन 80डी के तहत मेडिकल इंश्योरेंस पर मिलने वाला डिडक्शन भी क्लेम नहीं कर पाएंगे। सेक्शन 80डीडी तथा 80डीडीबी के तहत डिसेबिलिटी के लिए मिलने वाला टैक्स छूट भी नहीं ले पाएंगे।
- सबसे लोकप्रिय टैक्स छूट 80सी का फायदा भी नए टैक्स विकल्प में नहीं मिलेगा।
- सेक्शन 80ई के तहत एजुकेशन लोन पर मिलने वाला टैक्स बेनिफिट भी क्लेम नहीं कर पाएंगे।
- आईटी ऐक्ट के सेक्शन 80जी के तहत चैरिटेबल इंस्टिट्यूशंस को दिए गए दान पर मिलने वाले टैक्स छूट का फायदा भी नहीं मिल पाएगा।
- आयकर अधिनियम के चैप्टर 6ए के तहत मिलने वाले तमाम डिडक्शंस जैसे सेक्शन 80सी, 80सीसीसी, 80सीसीडी, 80डी, 80डीडी, 80डीडीबी, 80ई, 80ईई, 80ईईए, 80ईईबी, 80जी, 80जीजी, 80जीजीए, 80जीजीसी, 80आईए, 80-आईएबी, 80-आईएसी, 80-आईबी, 80-आईबीए इत्यादि का फायदा आप नए टैक्स विकल्प में नहीं उठा पाएंगे।

घर खरीदार को राहत : लोन ब्याज पर टैक्स लाभ की अवधि 31 मार्च 2021 तक बढ़ी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2020 पेश करते हुए कहा कि हाउजिंग लोन के ब्याज भुगतान पर मिलने वाली 3.5 लाख रुपए तक के टैक्स छूट को 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है। पिछले बजट में निर्मला सीतारमण ने हाउजिंग लोन के ब्याज पर टैक्स छूट सीमा को 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 3.5 लाख रुपए कर दिया गया था। मोदी सरकार ने जुलाई 2014 में अपने पहले बजट में इसे 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए किया था। होम लोन के प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों के रीपेमेंट पर टैक्स बचाने की सुविधा मिलती है। एक सेल्फ-ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए आपके होम लोन के इंट्रेस्ट के रीपेमेंट के लिए, आईटी ऐक्ट के तहत आपकी टोटल इनकम में से डिडक्शन के रूप में ज्यादा से ज्यादा 2 लाख रुपए तक क्लेम किया जा सकता हैए जिसे बढ़ाकर अब 3.5 लाख रुपए कर दिया गया था। सरकार के इस ऐलान का फायदा मिडिल क्लास के उन घर खरीदारों को मिलेगा जो 31 मार्च 2021 से पहले लोन लेकर 45 लाख रुपए तक का घर खरीदते हैं। हाउजिंग लोन पर ब्याज के भुगतान के बदले वह 1.5 लाख रुपए अधिक डिडक्शन प्राप्त करेंगे। मौजूदा इनकम टैक्स कानून होम लोन्स पर कई तरह के टैक्स लाभ देता है जो घर के प्रकार पर निर्भर करता है, जैसे घर अपने रहने के लिए खरीद रहे हैं या किराये पर लगाने के लिए।

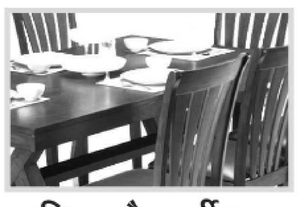

इस साल राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3.8 प्रतिशत रहने का अनुमान। अगले साल 3.5 प्रतिशत का लक्ष्य

बजट में फुटवियर और फर्नीचर पर आयात शुल्क बढ़ाया गया

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को आम बजट 2020.21 पेश करते हुए फर्नीचर और फुटवियर के आयात पर शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव किया। अपने दूसरे बजट भाषण में वित्त मंत्री ने चिकित्सा उपकरणों के आयात पर स्वास्थ्य उपकर भी लगाने की घोषणा की। अस्वस्थ महसूस होने के चलते

बजट में एमएसएमई के लिए आई गुड न्यूज, जल्द लागू होगी लॉजिस्टिक्स पॉलिसी

निर्मला सीतारमण ने सिंगल विंडो वाले ई-लॉजिस्टिक्स बाजार का गठन करने, रोजगार सृजन को बढ़ावा देने और एमएसएमई को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए जल्द ही एक राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति लाने की घोषणा की। वित्त मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति जल्दी ही जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित नीति में केंद्र सरकारए राज्य सरकारों तथा प्रमुख नियामकों

उद्यमियों के लिए निवेश मंजूरी प्रकोष्ठ बनेगा

वित्त मंत्री ने उद्यमियों के लिए निवेश मंजूरी प्रकोष्ठ के गठन का प्रस्ताव किया है। वित्त वर्ष 2020-21 का बजट पेश करते हुए सीतारमण ने कहा कि इस प्रकोष्ठ के जरिये उद्यमियों को जमीन और मंजूरियों के बारे निवेश पूर्व सलाह और सूचना दी जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा, मैं निवेश मंजूरी प्रकोष्ठ के गठन का प्रस्ताव करती हूं जो निवेश पूर्व सलाह देगा। यह प्रकोष्ठ उद्यमियों को जमीन तथा केंद्र और राज्य स्तर पर मंजूरियां

अखबारी कागज पर आयात शुल्क घटाने का प्रस्ताव

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न्यूजप्रिंट अखबारी कागज पर आयात शुल्क घटाकर पांच प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया है। सरकार ने पिछले साल बजट में न्यूजप्रिंट और हल्के कोटेड कागज पर 10 प्रतिशत का सीमा शुल्क लगाया था। सीतारमण ने 2020-21 का बजट पेश करते हुए कहा, मुझे बताया गया है कि इस शुल्क से मुश्किल समय में प्रिंट मीडिया पर अतिरिक्त बोझ पड़ा है। इसी के मद्देनजर मैं न्यूजप्रिंट ओर हल्के कोटेड कागज पर सीमा शुल्क 10 से घटाकर पांच प्रतिशत करने का प्रस्ताव करती हूं। इंडियन न्यूजपेपर सोसायटी आईएनएस ने इससे पहले सरकार से कहा था कि वह समाचार पत्र उद्योग को बचाने के लिए अखबारों के प्रकाशन में काम आने वाले लिए न्यूजप्रिंट और अनकोटेड कागज तथा पत्रिकाओं के प्रकाशन में काम आने वाले हल्के कोटेड कागज पर सीमा शुल्क को पूरी तरह समाप्त करे। आईएनएस ने कहा कि देश में मानकीकृत न्यूजप्रिंट की खपत 25 लाख टन की हैं घरेलू स्तर पर मिलों की क्षमता सिर्फ10 लाख टन उत्पादन की है।

सरकार ने सौर सेल, पैनल पर 20 प्रतिशत सीमा शुल्क हटाया

बजट में सौर सेल और पैनल पर 20 प्रतिशत आयात शुल्क हटाने की घोषणा की। यह तत्काल प्रभाव

श्री गुरू रविदास जी महाराज के प्रकाश उत्सव से संबंधित 8 फरवरी को शोभायात्रा के लिए कड़े प्रबंध किये जायें -विधायक सुशील कुमार रिंकू

रिंकू द्वारा शोभा यात्रा से संबन्धित आधिकारियों के साथ की मीटिंग

■ जालन्धर/प्रभातसूरी

विधानसभा क्षेत्र जालंधर पश्चिमी के विधायक श्री सुशील कुमार रिंकू ने आधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिये कि श्री गुरु रविदास जी महाराज के प्रकाश उत्सव से संबन्धित 8 फरवरी को निकाली जा रही शोभा यात्रा के लिए पुख्ता प्रबंधों को विश्वसनीय बनाया जाये। विधायक रिंकू जिन के साथ अतिरि1त डिप्टी कमिशनर (जनरल) जसबीर सिंह, डिप्टी कमिश्नर पुलिस नरेश कुमार डोगरा भी उपस्थित थे ने नजदीक रविदास चौक में आधिकारियों की मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए कहा कि सिविल, पुलिस और नगर निगम की तरफ से श्री गुरु रविदास जी महाराज के प्रकाश उत्सव से संबन्धित आयोजित की जा रही शोभायात्रा को सुचारू ढंग से पूर्ण करने के लिए जरुरी प्रबंध किये जाएंगे।

श्री रिंकू ने पुलिस विभाग को कहा कि शोभा यात्रा जोकि शहर के अलग अलग स्थानों से होती हुई गुजरेगी के दौरान सुरक्षा के पूर्ण प्रबंध करने के अतिरिक्त महिला पुलिस कर्मचारियों को भी तैनात किया जाये। उन्होने पुलिस विभाग को यह भी कहा कि शोभा यात्रा के दौरान यातायात को निर्विघ्न चलाने के लिए रूट भी तबदील किये जायें। इस तरह श्री रिंकू ने नगर निगम जालंधर को शोभा यात्रा के रास्तों की साफ सफाई, पीने वाले पानी और सजावट को भी विश्वसनीय बनाने के लिए कहा गया। उन्होने बिजली बोर्ड के आधिकारियों को कहा कि शोभा यात्रा और समागम के दौरान निर्विघ्न बिजली सप्लाई के अतिरि1त ढीले तारों की मुरम्मत को विश्वसनीय बनाया जाये। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के आधिकारियों को कहा कि डाक्टरी सहायता टीम भी तैनात की जाये। श्री रिंकू ने जिला प्रशासन को कहा कि समागम को पूरे धार्मिक रीति रिवाजों अनुसार मनाने के लिए जरुरी प्रबंध किये जायें। श्री रिंकू ने मीटिंग के दौरान अलग-अलग संस्थाओं के प्रतिनिधियों को विश्वास दिलवाया कि जिला प्रशासन द्वारा शोभा यात्रा और राज्य स्तरीय समागम के लिए पुख्ता प्रबंध किये जाएंगे। इस अवसर पर अतिरिक्त कमिशनर नगर निगम बबीता कलेर, एस.डी.एम.जलंधर-1 डा.जय इन्द्र सिंह, ए.डी.सी.पी. पी.एस.भंडाल, सहायक कमिशनर पुलिस एच.एस.भल्ला, सहायक सिविल सर्जन डा.गुरमीत कौर दुग्गल और अन्य भी उपस्थित थे।

बड़ी मछली क्यूं नहीं फँसती जाल में

■ जालंधर/विजय कुमार

छापा पड़ने की सूचना समय पूर्व ही पहुँच चुकी होती

प्राय: समाचार पढ़ने को मिलता रहता है कि आज 3 कर्मचारी विजीलैंस विभाग ने पकड़े रंगे हाथों पर यह कभी पढ़ने को नहीं मिलता कि आज इतने अधिकारी पकड़े गये लेकिन हाथ साफ थे क्यूंकि हाथ तो तभी रंगे जायेंगे न जब वह रंगीन नोट स्वयं पकड़ेंगे नोट पकड़ने को तो छोटे कर्मचारी जिन्हे विश्वस्त कर्मचारी कह सकते हैं साहब के कृपा पात्र जो साहब के लिये यह जोखिम उठाने को सदैव तत्पर रहते हैं हर विभाग में ऐसे चहेते कर्मचारी अवश्य होते हैं इन्हें भी हाथ रंगने के जोखिम का कुछ मुआवजा साहब द्वारा प्राप्त की जाने वाली किशत से मिलता है। इसे मिलता तो कुछ ही प्रतिशत है पर सजा शत प्रतिशत उसे ही मिलती है कुछ विभागों में तो इस छापा पड़ने की सूचना समय पूर्व ही पहुँच चुकी होती है। यह कैसे संभव होता है इसे पाठक निजी संज्ञान द्वारा ही जान सकते हैं कि वे कौन है जो संदेश वाहक का कार्य करते हैं इन विभागों में अधिकारियों को सर्तक रहने को , यह तो गलत है न कि करे कोई भरे कोई सरकार एंव जनता को इस पर विचार करना ही होगा अन्यथा मुन्शी प्रेम चन्द की कहानी जुर्माना चरितार्थ होती रहेगी और हम सब पढ़कर भूलते रहेंगे।

पंजाब सरकार द्वारा पहला दो दिवसीय 'अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल' मार्च में करवाया जायेगा-चन्नी

पंजाबी मातृभाषा को समर्पित फिल्म फेस्टिवल आई.के.जी. पी.टी.यू कपूरथला में 16-17 मार्च को करवाया जाऐगा

■ चंडीगढ़/चंदन

पंजाब सरकार द्वारा पहला दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय फि्ल्म फेस्टिवल 16 और 17 मार्च, 2020 को आई.के.जी.पी.टी.यू कपूरथला में करवाया जायेगा। आज यहाँ पर्यटन और सांस्कृतिक मामलों के मंत्री स. चरनजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व में पंजाब फ़िल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन, एस.ए.एस. नगर मोहाली और नॉर्थ जोन फ़िल्म और टी.वी. कलाकार एसोसिएशन, मोहाली के प्रतिनिधियों के साथ हुई मीटिंग के दौरान यह फ़ैसला लिया गया।

इस सम्बन्धी जानकारी देते हुये पर्यटन और सांस्कृतिक मामलों के मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व में करवाया जाने वाला यह मेला पंजाबी मातृभाषा को समर्पित होगा। उन्होंने साथ ही बताया कि पहले यह मेला 21 फरवरी, 2020 को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मौके करवाये जाने का प्रस्ताव था, परन्तु तैयारियों के लिए समय की कमी के कारण यह मार्च में करवाया जायेगा।

मंत्री ने बताया कि यह मेला पर्यटन और सांस्कृतिक मामलों के विभाग द्वारा पंजाब फ़िल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन, एस.ए.एस. नगर मोहाली और नॉर्थ जोन फ़िल्म और टी.वी. कलाकार एसोसिएशन, मोहाली के सहयोग से करवाया जायेगा।

उन्होंने बताया कि पंजाबी फ़िल्म उद्योग से सम्बन्धी दस्तावेज़ी फ़िल्म तैयार की जा रही है जो इस मेले के दौरान विशेष तौर पर दिखाई जायेगी, इसके साथ ही नामवर पंजाबी फिल्में दिखाई जाएंगी। मेले के दौरान पंजाबी फिल्मों की अलग-अलग कैटागिरियों के अनुसार इनाम दिए जाएंगे और कलाकारों को बैस्ट अभिनेता, बैस्ट ऐक्टरस, कॉमेडी कलाकार, सहायक कलाकार आदि की अलग-अलग कैटागिरियों के अनुसार इनाम दिए जाएंगे।

इस मौके पर अन्यों के अलावा राहुल तिवाड़ी सचिव रोज़गार सृजन विभाग, लखमीर सिंह अतिरिक्त डायरैक्टर पर्यटन और सांस्कृतिक मामलों के विभाग, मुनीश साहनी प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर, चरनजीत सिंह वालिया पंजाब फ़िल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन, हरमनप्रीत सिंह प्रोड्यूसर, मलकीथ रौनी कलाकार, जे.एस. चीमा डायरैक्टर / प्रोड्यूसर, हरबखश सिंह लाटा डायरैक्टर / प्रोड्यूसर, दलजीत अरोड़ा प्रैस सचिव नॉर्थ जोन फ़िल्म और टी.वी कलाकार ऐसोसिएशन और पर्यटन और सांस्कृतिक मामलों के विभाग के अधिकारी भी हाजिर थे।

राणा के.पी सिंह द्वारा भारत और कनाडा के आपसी संबंधों को और मज़बूत करने पर ज़ोर

ब्रैंपटन के एम.एल.ए अमरजोत संधू द्वारा विधानसभा स्पीकर के साथ मुलाकात

■ चंडीगढ़/चंदन

ब्रैंपटन पश्चिमी के एम.एल.ए (एम.पी.पी) अमरजोत संधू ने मंगलवार को यहां विधान सभा स्पीकर राणा के.पी सिंह के साथ मुलाकात की और उनको प्रवासी भारतीयों के विभिन्न मुद्दों से अवगत करवाया। ज़िक्रयोग्य है कि श्री संधू ऐसा पहला कैनेडियन अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी है जो ओंटारीयो की लैजिसलेटिव असेंबली में चुना गया है। कैनेडियन विधायक का स्वागत करते हुये स्पीकर ने कहा कि भारत और कैनेडा के बीच लम्बे समय से लोकतांत्रिक और बहुलवाद की साझी परंपराओं पर आधारित बहुत गहरी सांझ रही है। उन्होंने आगे कहा कि कैनेडा पंजाबियों के लिए दूसरे घर जैसा है और विदेशों में पंजाबियों को आगे विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ते देख कर बहुत खुशी मिलती है। श्री अमरजोत संधू कैनेडियन राजनीति में पंजाबियों की मज़बूत हाज़िरी की जीवित उदाहरण हैं। राणा के.पी. सिंह ने कहा कि भारत और कैनेडा को आपसी संबंधों को और मज़बूत करने के लिए सांझे हितों के और %यादा मौके तलाशने की ज़रूरत है। श्री संधू ने प्रवासी भारतीयों के कल्याण के लिए पंजाब सरकार द्वारा उठाये कदमों पर भी तसल्ली अभिव्यक्त की। पंजाब विधान सभा के स्पीकर राणा के.पी सिंह ने विधायक को यादगारी चिन्ह देकर सम्मानित किया। श्री संधू के साथ बाबा बकाला के विधायक श्री संतोख सिंह भलाईपुर भी मौजूद थे। उन्होंने पंजाब विधान सभा के असेंबली हॉल का दौरा भी किया और पंजाब विधान सभा सचिव श्रीमती शशि लखनपाल मिश्रा ने विधान सभा के इतिहास और मौजूदा बनावट संबंधी जानकारी दी।

स्पोर्ट्स

टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका, वनडे और टेस्ट सीरीज से बाहर हुए रोहित शर्मा

■ नई दिल्ली/ब्यूरो

भारत के सीमित ओवरों के उप कप्तान रोहित शर्मा रविवार को पांचवें और अंतिम टी20 अंतरराष्ट्रीय के दौरान पिंडली में लगी चोट के कारण न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी एकदिवसीय और टेस्ट श्रृंखला से बाहर हो गए हैं। माउंट मोनगानुई में मैच के दौरान तेजी से एक रन लेने के प्रयास में रोहित की पिंडली की मांसपेशियों में खिंचाव आ गया था और उन्हें 41 गेंद में 60 रन बनाने के बाद रिटायर्ड हर्ट होकर लौटना पड़ा था।

बीसीसीआई के सूत्र ने नाम जाहिर नहीं करने की शर्त पर बताया कि वह दौरे से बाहर हो गया है।

भारत को बुधवार से तीन एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला खेलनी है जबकि इसके बाद दो टेस्ट की श्रृंखला होगी।

एकदिवसीय श्रृंखला से टी-20 विश्वकप का अभ्यास नहीं, उसके लिए आई.पी.एल. है-कोहली

■ हैमिल्टन/ब्यूरो

भारतीय कप्तान विराट कोहली ने मंगलवार को कहा कि उनकी टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ एकदिवसीय श्रृंखला से टी20 विश्व कप की तैयारियों को मजबूत करने की योजना नहीं बना रही क्योंकि आगामी आईपीएल उसके लिए 'सही मंच' है। मुख्य कोच रवि शास्त्री ने हालांकि पिछले महीने कहा था कि न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका (मार्च में) के खिलाफ एकदिवसीय श्रृंखला का इस्तेमाल भारतीय टीम अक्टूबर-नवंबर में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाले टी20 विश्व कप के लिए करेगी। कोहली ने बुधवार को यहां पहले एकदिवसीय की पूर्व संध्या पर कहा, '' हम पहले ही पांच टी20 मैच खेल चुके हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास टी20 के पर्याप्त मैच नहीं है। हमारे पास आईपीएल भी है और यह डेढ़ महीने तक चलेगा। तो हम शायद उसका उपयोग करेंगे।'' भारतीय कप्तान ने कहा, ''जैसा कि मैंने कहा टी20 अलग तरह का प्रारूप है। आईपीएल शायद सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी टूर्नामेंट है। खिलाड़ी उस टूर्नामेंट में उस मानसिकता (टी-20 विश्प कप की तैयारी) के साथ उतरेंगे। अभी विश्व कप में काफी समय है और हम अभी उस मानसिकता में आकर 50 ओवर के प्रारूप में अलग तरीके से नहीं खेलना चाहते हैं।'' कप्तान को लगता है कि प्रत्येक प्रारूप को एक जैसा सम्मान देना जरूरी है। उन्होंने कहा, ''आपको हर प्रारूप का सम्मान करना होगा, आपको 50 ओवर के खेल की उसकी गति के अनुसार खेलना होगा। जैसा कि मैंने संयोजन के बारे में बात की, यह खिलाड़ियों को उनकी भूमिकाओं में ढलने और उसे दोहराने के बारे में है ताकि उन्हें पता चले कि उन्हें किस प्रारूप में कैसे खेलना है।'' न्यूजीलैंड को टी20 श्रृंखला में 5-0 से हराने के बाद भारतीय टीम एकदिवसीय श्रृंखला में बढ़े हुए आत्मविश्वास के साथ जाएगी। कोहली की टीम ने न्यूजीलैंड के पिछले दौरे पर एकदिवसीय श्रृंखला में 4-1 से जीत दर्ज की थी। कोहली ने कहा, ''पिछली बार जब हम यहां खेले थे, तो हम पहले तीन मैचों में हावी थे। चौथे मैच में हार का सामना करना पड़ा और पांचवें में हमने फिर से वापसी की। हमने महसूस किया कि वास्तव में वनडे में हमारे पास योजनाओं को पूरा करने के लिए अधिक समय है। टी20 प्रारूप न्यूजीलैंड के लिए उपयुक्त था क्योंकि वे विस्फोटक क्रिकेट खेल सकते थे। एकदिवसीय क्रिकेट में हमने कुछ बहुत ही कठिन श्रृंखलाएं खेली हैं।'' कप्तान ने कहा कि टी20 में बुरी तरह से हारने के बाद न्यूजीलैंड की टीम वापसी को बेकरार होगी। उन्होंने कहा, ''यह कुछ ऐसा है जिससे हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। हम अपनी योजनाओं पर विश्वास करने के साथ उन दबाव के क्षणों को अपने पक्ष में बदलने की कोशिश करते हैं। न्यूजीलैंड की टीम भी कभी हार नहीं मानती और वापसी के तरीके खोजती रहती है।'' भारतीय टीम के क्षेत्ररक्षण का स्तर पिछले कुछ समय में गिरा है लेकिन टीम ने बीच-बीच में गजब का प्रदर्शन किया है। कोहली ने कहा कि टीम प्रबंधन ने इस पर ध्यान दिया है तथा बल्लेबाजी और गेंदबाजी के साथ क्षेत्ररक्षण में सुधार की कोशिश की जा रही।

Lic No : 933/ALC-4/LA/FN:1184

INNOVATIVE TECHNO INSTITUTE

CONSULTING DESIGN TRAINING

INNOVATIVE TECHNO INSTITUTE

ISO CERTIFIED 2015 COMPANY

IELTS • PTE • TOEFL

SPOKEN ENGLISH

TOURIST VISA | STUDY VISA | PR

WORK PERMIT | HOLIDAY PACKAGES

CANADA AUSTRALIA USA U.K SINGAPORE EUROPE

9988115054 • 9317776663

REGIONAL OFFICE : S.C.O No. 10, Gopal Nagar, Near Batra Palace, Jal.

HEAD OFFICE : S.C.O No. 21-22, Kuldip Lal Complex, Highway Plaza, GT Road, Adjoining Lovely Professional University, Phagwara.

E-mail : ankush@innovativetechin.com • hr@innovativetechin.com

Website : www.innovativetechin.com • FB/Innovativetechin